प्रवाह

अमर उजाला

नई दिल्ली ■ मंगलवार, 13 सितंबर 2016

निर्भीक पत्रकारिता के 67 साल

स्थापना वर्ष : 1948

सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने जीवन का आनंद उठाएं और हमेशा खुश रहें

... आद्रे हेपबर्न

इस मौसम में इन बीमारियों का प्रकोप कोई नई बात नहीं, लेकिन अमूमन दक्षिणी राज्यों को प्रभावित करने वाले चिकनगुनिया के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते मामलों से पता चलता है कि ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए व्यापक रणनीति की जरूरत है।

व्यवस्था के इलाज का सवाल

इस वर्ष अच्छे मानसून के बाद देश की राजधानी दिल्ली सहित अनेक राज्यों में जिस तरह से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि मच्छरों के काटने से होने वाली इन बीमारियों से निपटने का कारगर तरीका ढूंढना तो दूर, इनसे बचने के एहतियाती कदम तक समय पर नहीं उठाए गए हैं। इस मौसम में इन बीमारियों का प्रकोप कोई नई बात नहीं, लेकिन अमूमन दक्षिणी राज्यों को प्रभावित करने वाले चिकनगुनिया के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते मामलों से पता चलता है कि ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए व्यापक दूरगामी रणनीति की जरूरत है। पूरे देश में इस वर्ष चिकनगुनिया के 12 हजार और डेंगू के 28 हजार से अधिक मरीज अस्पतालों तक पहुंच चुके हैं! मुश्किल यह है कि एडिस नामक मच्छर की विभिन्न प्रजातियों के काटने से होने वाले डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए अब तक कोई टीका ईजाद नहीं किया जा सका है। मच्छरों से होने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि गंदा पानी या गंदगी जमा न हो, लेकिन हालत यह है कि देश में स्वच्छ भारत अभियान जैसा कार्यक्रम चलने के बावजूद न तो नगर प्रशासन और न ही नागरिक तक इसे स्वास्थ्य से जोड़ने को तैयार दिख रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप के बीच ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा श्रीलंका को मलेरिया से मुक्त घोषित करने की खबर आई है। श्रीलंका में 2012 के बाद से मलेरिया का एक भी मामला सामने नहीं आया। मगर हमारे यहां हालत यह है कि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों को तो छोड़ें, राजधानी दिल्ली तक मलेरिया से प्रभावित है, जहां इस बीमारी से कुछ दिनों के भीतर ही दो लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्तर पर इन संक्रमण जनित रोगों से निपटने के लिए कार्यक्रम न चलाए गए हों, लेकिन इन कार्यक्रमों को सरकारी ढर्रों से निकालने की जरूरत है। हम स्मार्ट सिटी जैसा सपना देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ बहुमंजिली इमारतें और चमचमाती सड़कें ही इसका हिस्सा नहीं हो सकतीं, इसके लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी प्राथमिकता में रखा जाए। एक अच्छे मानसून का मतलब खराब स्वास्थ्य नहीं होना चाहिए।

घाटी से बाहर भी देखिए

केंद्र सरकार को राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए और कश्मीर घाटी में चंडीगढ़ की तरह एक केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर उसमें कश्मीरी पंडितों और शेष भारत के इच्छुक लोगों को बसाना चाहिए।

अग्निशेखर, पनून कश्मीर के नेता

जम्मू-कश्मीर में जारी अशांति और हिंसा के बीच पिछले दिनों जो सर्वदलीय शिष्टमंडल राज्य के दौरे पर आया, उसने कश्मीरी पंडितों के विभिन्न संगठनों की उपेक्षा की, जिसके चलते कश्मीरी पंडितों के संगठन पनून कश्मीर ने सर्वदलीय शिष्टमंडल का बहिष्कार किया और बताया कि यह कश्मीरी पंडितों की आंखों में धूल झोंकने के समान है। इस शिष्टमंडल के आने से पहले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह दो बार राज्य के दौरे पर आए थे, लेकिन उन्होंने जम्मू और लद्दाख की जनता की पूरी तरह से अनदेखी की। इससे इस क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी थी, क्योंकि आज कश्मीर घाटी में अशांति और हिंसा का जो माहौल है, उससे सिर्फ घाटी के लोग ही परेशान नहीं हैं, बल्कि पूरे राज्य के लोगों पर उसका असर पड़ रहा है। जब इस नाराजगी को भाजपा के भीतर के ही किसी नेता ने सामने रखा, तभी बेमन से कश्मीरी पंडितों और जम्मू के संगठनों से बातचीत करने का मन बनाया गया।

बेमन से इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के विभिन्न संगठनों के बारह प्रतिनिधियों को शिष्टमंडल से मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्हें मात्र आठ मिनट का समय दिया गया। अब समझा जा सकता है कि अलग-अलग राजनीतिक दलों और विचारधारा के ये बारह प्रतिनिधि मात्र आठ मिनट में अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से शिष्टमंडल के सामने कैसे रख सकते थे। कश्मीरी पंडितों को सर्वदलीय शिष्टमंडल से मिलने के लिए बुलाकर सिर्फ यह दिखाने का प्रयास किया गया कि इस वार्ता में राष्ट्रवादियों को भी शामिल किया गया है। जबकि दूसरी ओर शिष्टमंडल के कई सदस्य खुद ही उन अलगाववादियों से मिलने गए, जो हमेशा भारत विरोध की बातें करते हैं और कश्मीर घाटी को अराजकता की ओर धकेल रहे हैं। विडंबना देखिए कि उन अलगाववादियों ने शिष्टमंडल के सदस्यों के लिए अपने दरवाजे तक नहीं खोले, बात करना तो दूर की बात।

हुर्रियत और अन्य अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत करने का क्या मतलब है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता नहीं, बल्कि कश्मीर में इस्लामी कानून चलाना चाहते हैं? वे इस्लामी शासन की स्थापना के लिए आजादी की मांग करते हैं और छोटे-छोटे बच्चों को आगे करके सुरक्षा बलों पर पत्थर चलवाते हैं। खुद पीडीपी के एक सांसद ने संसद में बहस के दौरान कहा कि कश्मीर घाटी में आज जो रहा है, वह सौ फीसदी इस्लामी फासीवाद है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर फारूक ने ट्वीट किया कि कश्मीर में जारी अशांति पूरी तरह भारत-विरोधी है। फिर भी भारत सरकार इन अलगाववादी नेताओं की सुख-सुविधा पर सालाना सौ करोड़ रुपये खर्च करती है, जबकि जम्मू और लेह के लोग, जो राष्ट्रवादी हैं, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक बहुलता में विश्वास करते हैं, उनकी अपेक्षा की जाती है। आज कश्मीर घाटी तो जल ही रही है, जम्मू और लेह-लद्दाख क्षेत्र की अनदेखी के कारण यहां भी लोगों में भारी असंतोष है। भाजपा ने चुनाव से पहले जो घोषणाएं की थीं, उन्हें पूरा नहीं किया गया। जम्मू क्षेत्र में एक एम्स बनाने की योजना थी, पर पीडीपी-भाजपा सरकार उसे भी कश्मीर क्षेत्र में ले गई।

दरअसल पीडीपी के साथ राज्य में सरकार बनाना भाजपा के लिए भी और राज्य की शासन व्यवस्था के लिए भी आत्मघाती साबित हुआ। भाजपा के नेता पहले पीडीपी को नरम अलगाववादी या परोक्ष अलगाववादी कहते थे, क्योंकि पीडीपी का रवैया हमेशा से अलगाववादियों के प्रति नरम रहा है। सरकार गठन के समय पीडीपी और भाजपा के बीच जिस एजेंडा फॉर एलायंस पर सहमति बनी, उसमें साफ-साफ लिखा है कि राज्य की गठबंधन सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसले पर होने वाली वार्ता में सहयोग करेगी, यानी राज्य सरकार को एक तीसरा पक्ष बना दिया गया। दूसरी बात यह है कि सरकार कश्मीर में शांति और विकास के लिए सभी पक्षों यानी अलगाववादियों से भी बातचीत करेगी। तीसरी बात यह कि धीरे-धीरे राज्य के विभिन्न इलाकों से सेना हटाई जाएगी और चौथी बात, गठबंधन सरकार अशांत घोषित क्षेत्रों को डिनोटिफाइंग क्षेत्र घोषित करने की जरूरत की समीक्षा करेगी। सभी जानते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऐक्ट को लेकर भाजपा और पीडीपी, दोनों का रुख अलग-अलग था, लेकिन सत्ता पाने के लिए दोनों ने गठजोड़ किया।

भाजपा-पीडीपी सरकार के बनते ही घाटी में अलगाववादियों के हौसले बढ़ गए। विभिन्न जगहों से सेना को हटा लिया गया और बंकरों को खत्म किया गया, जिसका अलगाववादियों ने जश्न मनाया। आज स्थिति यह है कि राज्य पुलिस डर के कारण अपना आई कार्ड तक नहीं दिखाती है। घाटी में चल रहे इस अराजक आंदोलन का नेतृत्व अब कट्टरपंथी बन चुके युवाओं के हाथों में चला गया है, जो पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान से प्रभावित हैं। गौरतलब है कि पिछले चीन-चार वर्षों से पूरी घाटी में वहाबी कट्टरपंथ तेजी से बढ़ा है। दुखद है कि ऐसे नाजुक क्षण में भी राज्य की विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाने में लगी हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ऐसा करके वे राज्य को अराजकता की दिशा में धकेल रहे हैं। तो फिर उपाय क्या है? अगर कश्मीर में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और बहुलता को बचाना है, तो केंद्र सरकार को राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए और कश्मीर घाटी में चंडीगढ़ की तरह एक केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर उसमें कश्मीरी पंडितों और शेष भारत के इच्छुक लोगों को बसाना चाहिए। इसके अलावा घाटी में हवाला से आने वाले धन पर रोक लगानी चाहिए और अलगाववादियों के पास जो इतनी अकूत संपत्ति जमा हो गई है, उसकी जांच करनी चाहिए।

सबसे दयालु आग मां के हृदय और चूल्हे में

अंतर्ध्वनि

>> रसूल हमजातोव

***आग** के साथ खिलवाड़ मत करो, मेरे पिता जी कहा करते थे। पानी में कंकड़-पत्थर न फेंको, अम्मा अनुरोध किया करती थीं। विभिन्न लोगों को उनकी मां विभिन्न रूपों में याद आती है। मैं अपनी मां को सुबह, दोपहर और शाम को याद करता हूं। सुबह वह पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर चश्मे से लौटती थीं। वह बहुत ही कीमती चीज की तरह उसे लेकर आती थीं। वह पत्थर की सीढ़ियां चढ़तीं, घड़े*

को जमीन पर रख देतीं और चूल्हे में आग जलाने लगतीं। आग भी वह बहुत ही कीमती चीज की तरह जलातीं। वह कभी चिंता तो कभी मुग्ध भाव से उसकी ओर देखतीं। आग के अच्छी तरह से जल जाने तक अम्मा पालना झुलाती रहतीं। दोपहर के वक्त अम्मां खाली घड़ा लेकर पानी लाने को चश्मे पर जातीं। इसके बाद आग जलातीं, फिर पालना झुलातीं। शाम को अम्मा घड़े में पानी लातीं, पालना झुलातीं, आग जलातीं। वह वसंत, गर्मी, पतझर और जाड़े में हर दिन ऐसा ही करतीं। वह धीरे-धीरे, बड़ी गंभीरता से ऐसा करतीं जैसे कि कोई बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण काम कर रही हों। मेरे मन में मेरी मां की स्मृति इसी रूप में अंकित है। पानी लाने के लिए जाते वक्त वह हमेशा मुझसे कहती थीं, आग का ध्यान रखना। इसे बुझने नहीं देना, पानी नहीं गिराना। वह कहा करती थीं- दागिस्तान के लिए आग पिता है, पानी मां है। पहाड़ी कहावत और पहाड़ी औरत के आंसू में भी आग होती है। पर सबसे दयालु और स्नेहपूर्ण आग मां के हृदय और हर घर के चूल्हे में होती है।

मंजिलें और भी हैं

>> ध्रुवज्योति सेन

गणित से बड़ी है जिंदगी की कक्षा

वह साइंस के जहीन छात्रों में था। इसलिए मैं तब अवाक रह गया था, जब उसने मुझे एक दिन बताया कि उसने पढ़ाई के बीच में विज्ञान छोड़कर मानविकी में दाखिला ले लिया। असल में उसके गरीब पिता विज्ञान की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। एक शिक्षक ने उसे मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाने का जिम्मा भी लिया था। वह उनकी क्लास में जाता था। लेकिन धीरे-धीरे उसे महसूस हुआ कि वह शिक्षक भी उससे कतराने लगे हैं। दरअसल वह उसके सवालों की अनदेखी करने लगे थे। जो छात्र मुफ्त में ट्यूशन पढ़ता हो, और दया का पात्र हो, उसे भला कौन महत्व देता है! एक-दो बार उस शिक्षक ने उसे जोर से डांट भी दिया, तो उसने ट्यूशन जाना छोड़ दिया। वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। फिर वही होना था, जो अक्सर गरीब छात्रों के मामले में होता है। उसने आर्ट्स में दाखिला लिया, क्योंकि उसमें फीस भी कम थी, किताबें भी महंगी नहीं थी और ट्यूशन के बिना भी पढ़ाई की जा सकती थी। बुद्धिमान, लेकिन गरीब छात्र यहीं आकर तो मात खा जाते हैं। जीवन के इसी मोड़ पर पैसे का महत्व पता चलता है। अगर आपके पास पैसा है, तो बिना प्रतिभा के भी आप साइंस पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोट्स, गाइड और ट्यूशन के लिए पैसे खर्च करने की आपमें क्षमता होती है। गरीब छात्र क्या करे? कहां जाए?

प्रतिभाशाली गरीब बच्चों को बेहतर मौका मिले, तो वे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।

हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तब हर साल कोर्स की किताबों में इतना बदलाव नहीं होता था। इसलिए पुरानी किताबों से भी काम चल जाता था। खुद मैं जब ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब मेरे चाचा की गणित की किताब मेरे काम आई थी। लेकिन अब पुरानी किताबें किसी काम की नहीं रह जातीं। किताबें महंगी भी तो बहुत हो गई हैं। स्कूल की गणित और विज्ञान की किताबों की कीमत चार-पांच सौ रुपये की हो गई हैं। पूरी किताबें और स्टेशनरी दो हजार रुपये तक की हो जाती हैं। स्कूल की फीस और प्राइवेट ट्यूशन का खर्च अलग से। ऐसे में ढाई-तीन हजार रुपये महीना कमाने वाले गरीब लोगों के बच्चे भला विज्ञान की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं?

मैं खुद हुगली के एक सरकारी स्कूल में गणित का शिक्षक हूं। इसलिए उस गरीब छात्र की मजबूरी को समझ सकता हूं। उस छात्र से मिलने के बाद कई दिनों तक मैं सोचता रहा कि उसके लिए क्या कर सकता हूं। आखिर में मैंने यह तय कर लिया कि अपनी सीमित आय से ही गरीब छात्रों की जितनी मदद हो सकेगी, करूंगा। मैंने ग्यारहवीं के प्रतिभाशाली, किंतु गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इससे खर्च पर असर पड़ा। जैसे, बीच-बीच में बाहर खाने की आदत छोड़नी पड़ी।

बाद में विज्ञान के तीन और शिक्षक मेरे इस अभियान से जुड़े, जिनमें से एक रिटायर्ड शिक्षक हैं। अभी हम हावड़ा, हुगली और कोलकाता के बच्चों को ही पढ़ा सक रहे हैं। हमें पता है कि इन इलाकों के जरूरतमंद छात्र अभी हम तक नहीं पहुंच पा रहे। मैंने फेसबुक पर भी अपील जारी की है, लेकिन सच्चाई यह है कि गरीब बच्चों की फेसबुक तक पहुंच नहीं है। मेरा मानना है कि इन प्रतिभाशाली गरीबों को बेहतर मौका मिले, तो वे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब अपने आसपास के ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा-सा वक्त तो निकाल ही सकते हैं।

बिजली खपत हो नीतियों के केंद्र में

हालांकि इस सुझाव पर अमल नहीं हो सका है, पर अभी अनेक सरकारी पहलों में ऊर्जा के उपयोग संबंधी क्षमता के जरिये ऊर्जा की मांग को फिर से केंद्र में रखा जा रहा है। साथ ही इसके उपयोग और वितरण पर भी विचार करना होगा।

राधिका खोसला

भारत की विकास संबंधी योजना में लंबे समय से बिजली (ऊर्जा) केंद्र में रही है। अधिकांश मामलों में बिजली के उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए कोयला, गैस, आणविक और नवीकरणीय स्रोत आदि को बढ़ाने पर विचार किया गया। ऊर्जा संबंधी मौजूदा योजनाओं के अहम तत्व भी इसी रुझान को दिखाते हैं : 2020 तक कोयले का घरेलू उत्पादन 1.5 अरब टन करने और 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 175 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा संबंधी योजना में आपूर्ति केंद्रित दृष्टिकोण दरअसल बिजली की दीर्घकालिक कमी से ही उपजा है। विशेष रूप से इसके केंद्र में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती जरूरतें और इसके मद्देनजर उपलब्ध ऊर्जा विकल्पों को खंगालने के प्रयास होते हैं। अक्सर इसके साथ यह विचार नहीं किया जाता कि ऊर्जा का उपयोग कहां होगा और इसकी लागत क्या आएगी।

भारत में ऊर्जा संबंधी योजना का इतिहास बताता है कि व्यापक रूप में आपूर्ति को ही ध्यान में रखा गया। 11 वीं और 12 वीं पंचवर्षीय योजनाएं इसका प्रमाण हैं। लेकिन इसके साथ ही एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है, जिसने ध्यान कम खींचा है। यह दृष्टिकोण सिर्फ इस पर केंद्रित नहीं है कि ऊर्जा की आपूर्ति किस तरह से होगी, बल्कि यह भी देखा गया कि इसका उपयोग किस तरह से होगा। 1980 के मध्य में अमूल्य रेड्डी ने इस पारंपरिक दृष्टिकोण को बदलकर सुझाव दिया कि ऊर्जा के स्रोत के बजाय ऊर्जा के उपभोग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस दृष्टिकोण में ऊर्जा संबंधी व्यवस्था और इसकी आपूर्ति और उपभोग संबंधी गतिविधियों का उद्देश्य प्रकाश, अनुकूल तापमान, रेफ्रीजरेशन और परिवहन जैसी ऊर्जा सेवाएं मुहैया करना है, ताकि विकास संबंधी लक्ष्य हासिल किए जा सकें। हालांकि रेड्डी के इस सुझाव पर अमल नहीं हो सका है, लेकिन अभी अनेक सरकारी पहलों में ऊर्जा के उपयोग संबंधी क्षमता के जरिये ऊर्जा की मांग को फिर से केंद्र में रखा जा रहा है।

भारत में, ऊर्जा की आपूर्ति कैसे होगी, इस विचार के साथ ही इसके उपयोग और इसके वितरण पर भी विचार करना, तीन कारणों से कहीं अधिक उत्पादक होगा। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था संक्रमण से गुजर रही है। जनसांख्यिकी रूप से देखें, तो भारत में अगले दो दशकों तक हर वर्ष रोजगार बाजार में एक करोड़ नए लोग कतार में होंगे। इसका खासतौर से असर मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में ऊर्जा के उपयोग पर होगा। ठीक इसी समय शहरीकरण के कारण तकरीबन 20 करोड़ लोग शहरी क्षेत्रों की ओर जाएंगे, जिससे बेहतर जीवन-शैली के अनुरूप संसाधनों की मांग भी बढ़ेगी। दूसरा कारण यह है कि ऊर्जा संबंधी योजना में मांग को केंद्र में रखने से न केवल ऊर्जा की आपूर्ति का प्रबंधन आसान होगा, बल्कि इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। और अंत में पारंपरिक आपूर्ति केंद्रित दृष्टिकोण भारतीय ऊर्जा जरूरतों का निदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, 40 करोड़ लोगों तक बिजली नहीं पहुंची है। बिजली की कमी की वजह से डीजल से चलने वाले जेनरेटर प्रदूषण फैला रहे हैं। जाहिर है, भारत को ऊर्जा संबंधी योजना पर दृढ़ता के साथ पुनर्विचार करना चाहिए।

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली की फेलो

हरियाली और रास्ता

मां के हाथों में सफलता की लकीर

यह कहानी एक गरीब विधवा के बेटे कमल की है।

***कमल** पढ़ाई में तेज था। हाई स्कूल से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर रिसर्च में वह हमेशा अव्वल ही था। सबको भरोसा था कि कमल का प्लेसमेंट बड़े आराम से हो जाएगा। उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू के पहले तीन राउंड पार भी कर लिए थे। आखिरी राउंड में कंपनी के डायरेक्टर खुद इंटरव्यू ले रहे थे। डायरेक्टर ने पूछा, 'क्या आपको कभी कोई स्कॉलरशिप मिली है?' कमल ने कहा, 'अब तक नहीं।'*

डायरेक्टर ने फिर सवाल किया-'स्कूल की फीस कैसे जमा की आपने। क्या आपके पिता

घर के खर्च संभालते थे?' कमल ने कहा, 'मैं एक साल का था, तभी मेरे पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद घर का खर्च मेरी मां पर निर्भर था।' डायरेक्टर ने पूछा, 'क्या करतीं हैं आपकी मां?' कमल ने बताया, 'सर वह लोगों के घरों में कपड़े धोती हैं?' डायरेक्टर ने कहा, 'क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूं?' कमल ने हाथ दिखा दिए। उसके हाथ एकदम साफ, मुलायम और बेदाग थे। डायरेक्टर ने पूछा, 'क्या आपने कभी कपड़े धोने में मां की मदद की?' 'मैंने कोशिश की, लेकिन मां चाहती थी कि मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूं।' डायरेक्टर ने कहा, 'आज मेरा एक काम करोगे? घर जाकर अपनी मां के हाथ अच्छे से साफ करना। और फिर कल आकर सुबह मुझसे मिलना।' कमल खुश था। उसे चयन की पूरी उम्मीद थी। घर लौटकर उसने मां से कहा, 'आज मैं आपके हाथ धोना चाहता हूं। मां को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा अटपटा भी। कमल ने देखा कि उसकी मां के हाथों में झुर्रियां पड़ गई थीं, कई जगह से कटे हुए, कई जगह गड्ढे भी पड़े थे। कमल की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार अपने हाथों में मां के हाथों को पकड़े वह उनका दर्द महसूस कर पा रहा था। उसको समझ आ गया था कि उसकी फीस मां कैसे चुका रही थी। उस दिन बाकी के बचे हुए सारे कपड़े खुद कमल ने धोए। रात में काफी देर तक कमल और उसकी मां बातें करते रहे। अगले दिन जब कमल डायरेक्टर के पास पहुंचा, तो डायरेक्टर उसकी सूजी हुई आंखें देखकर पूरी कहानी समझ गए। उन्होंने कमल से पूछा, ...तो कल के अनुभव से आपने क्या सीखा?' कमल ने कहा, 'मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं आज जो भी हूं, वह अपनी मां की वजह से हूं। और मुझे पहली बार परिवार की अहमियत समझ में आई।' डायरेक्टर बोले, 'मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था, जो रिश्तों और मूल्यों को पैसों से बढ़कर माने। हमारी कंपनी में तुम्हारा स्वागत है।'

पैसों के बजाय मूल्यों को महत्व देने वाले ज्यादा सफल होते हैं।

खुली खिड़की

महिला स्टार्टअप पीछे क्यों

देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ने इस साल 16 जनवरी को 'स्टार्टअप इंडिया' की शुरुआत की थी। इसके बाद तेजी से स्टार्टअप कंपनियां बनने लगीं। पर, ऐसा लगता है कि स्टार्टअप के बूम में महिलाएं अब भी पिछड़ी हुई हैं। दूसरी स्टार्टअप परियोजनाओं को फंड मिल रहा है, तो जबकि महिलाओं द्वारा संचालित उपक्रम निवेशकों को शायद आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं।

670

स्टार्टअप परियोजनाओं को वर्ष 2016 में फंडिंग हुई है।

556 स्टार्टअप कंपनियों के संस्थापक पुरुष हैं।

93 परियोजनाओं के संस्थापकों में महिला-पुरुष दोनों हैं।

21 स्टार्टअप कंपनियों की संस्थापक महिलाएं हैं।

विश्वास की नाव

एक बार की बात है। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने कमरे में बैठे थे। दिन के तीन बज रहे थे। राखाल, लाटू, मास्टर, महिमाचरण आदि भक्त भी उनके पास बैठे हुए थे। स्वामी जी उन्हें समझाते हुए कह रहे थे, भक्त के हृदय में विश्वास होना परम आवश्यक है। विश्वास वह शक्ति है, जो असंभव को संभव में परिवर्तित कर देती है। अगर विश्वास या भरोसा न हो, तो आधी जंग हम पहले ही हार जाते हैं। यदि शिष्य में गुरु के प्रति विश्वास हो, तो ही वह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भक्त में भी भगवान के प्रति विश्वास हो, तो वह भी उन तक पहुंच सकता है। सभी भक्त बड़ी तल्लीनता से उनकी बातें सुन रहे थे। स्वामी जी ने आगे कहा, जिसके अस्तित्व के प्रति मन में अविश्वास पैदा होता रहे, उसके साथ जुड़ा सूत्र भी बार-बार टूटता रहता है। जब मन में पूर्ण विश्वास उत्पन्न हो जाता है, तभी प्रेम पैदा होता है। अपनी बात समझाते हुए वह आगे बोले, यदि मां कहे कि वहां भूत है, तो ठीक मानो कि हां, वहां भूत है। मां कहे कि वहां हौआ है, तो यह ठीक ही मानो कि हां, वहां हौआ ही है। मां कहे कि यह तेरा दादा है, तो समझो कि सोलह आने यही मेरा दादा है। ऐसा दृढ़ विश्वास अगर ईश्वर पर भी पैदा हो जाए, तब उनके साथ भी निकटता बन जाती है। बहुत-से नेत्रहीन अथाह अंधकार में भी बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास विश्वास की ताकत होती है। इस प्रसंग से यह प्रेरणा मिलती है कि भक्त को अपने मन से अविश्वास का पर्दा हटाना होगा। जब वह पूर्ण रूप से अपने गुरु या ईश्वर पर विश्वास करेगा, तभी उनकी निकटता प्राप्त कर पाएगा।

सत्संग